इकाई 14 कंपनी की वाणिज्यिक नीतियाँ और भारतीय व्यापार

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे :

- बहुत से निवेशकों की सामूहिक पूँजी उद्यम के रूप में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना की गई,
- ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात इन पूँजीवादी सौदागरों को किस प्रकार तथा क्यों उनके क्रमशः अपने-अपने देशों की सरकारों के द्वारा व्यापार के विशेषाधिकारों पर एकाधिपत्य प्रदान किया गया,
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार एवं अंग्रेजी उन्मुक्त व्यापारियों के बीच संघर्ष कैसा था जिसके कारण व्यापार के विशेषाधिकारों पर एकाधिपत्य को वापस लिया गया,
- भारत में सामूहिक एकाधिकार के रूप में ब्रिटिश कंपनी के व्यापार एवं कंपनी के नौकरों के व्यक्तिगत व्यापार की प्रकृति,
- उन कारणों के विषय में जिनसे कि पूँजीवादी उद्यमी सौदागर क्षेत्रों तथा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुए, और
- औद्योगिक पूँजीवाद के उदय ने किस प्रकार से भारतीय ब्रिटिश आर्थिक संबंधों की प्रकृति को परिवर्तित किया और इसके फलस्वरूप कंपनी की वाणिज्य नीतियों में कैसे परिवर्तन हुए।

14.1 प्रस्तावना

आप पहले ही उन परिस्थितियों को जान चुके हैं जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आयी। यह यूरोप में सौदागर पूंजीवादी के लम्बे विकास का परिणाम थी (खंड 2)। आप यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों विशेषकर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अदा की गई उस भूमिका के विषय में भी जानते हैं जो उन्होंने 18वीं सदी के अन्तिम दशकों तथा 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत के राजनीतिक इतिहास में निभायी (खंड 3)। इस इकाई में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एवं इसके पास एकाधिकार की संरचना एवं प्रवृत्ति से आपका परिचय कराया जायेगा। कंपनी के द्वारा क्षेत्रों तथा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्यों, इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजीवादी का उद्भव और कम्पनी की वाणिज्य नीतियों में इसका प्रभाव, इन सबका इस इकाई में विवेचन किया गया है।

14.2 ईस्ट इंडिया कंपनी का ढाँचा

आपको यह भली भांति समझ लेना चाहिये कि आजकल व्यावसायिक उद्यमों में उन कंपनियों का प्रभुत्व है जो स्टॉकों एवं शेयर्स की बिक्री इसलिये करती हैं जिससे कि व्यवसाय में जरूरत पड़ने वाली पूँजी को एकत्रित कर सकें। ये संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ उनसे भिन्न हैं जिनमें व्यवसाय पर एक स्वामी या हिस्सेदारी में कुछ स्वामियों का अधिकार होता था। यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनियाँ विश्व में प्रारंभिक संयुक्त स्टॉक कंपनियों में से कुछ थीं।

इन कंपनियों की क्या विशेषता थी और इन्होंने अपने संयुक्त स्टॉक संगठन स्वरूप से कैसे लाभ प्राप्त किया? संयुक्त स्टॉक संरचना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसके अनुसार विभिन्न स्रोतों या शेयर धारकों से पूँजी को एकत्रित किया जाता है। ये कंपनियाँ फिर इस योग्य हो जाती हैं कि किसी एक मालिक या कुछ को हिस्सेदारी उपलब्ध कराके काफी बड़ी मात्रा में पूँजी को इकट्ठा कर सकती है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संयुक्त स्ट्राक कंपनियाँ व्यावसायिक गतिविधियों और नीतियों को काफी लंबे समय तक, कभी-कभी सदियों तक अनवरत रूप से चलाने को सुनिश्चित कर सकती हैं जबकि एक मालिक के अधीन व्यवसाय का जीवन काफी कम होता था। इसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि संयुक्त स्ट्रॉक कंपनी में पूँजी की गतिशीलता बनाए रखने की पर्याप्त संभावना होती है, दूसरे शब्दों में कंपनी के शेयर धारकों के रूप में निवेश किए गए धन को शेयर का मालिक वापस ले सकता है (अपने शेयर को दूसरे को बेचकर) दूसरी कंपनी में निवेश करने सहित वह उसको कहीं अन्य उपयोग में लगा सकता है इस प्रकार से पूँजी किसी एक ही उद्यम में बंधी नहीं रहती बल्कि वह अधिक लाभ देने वाले उद्यमों की ओर गतिशील होती रहती है। इस प्रकार पूँजी का अच्छी प्रकार से उपयोग सुनिश्चित होता जाता है।

इन सभी कारणों से ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनियों का स्वरूप पहले अन्य स्वरूपों की अपेक्षा अधिक सक्षम एवं उच्चतर था। विशेषकर भारत के साथ व्यापार के लिए यूरोपीय देशों को इस प्रकार संगठन के नए स्वरूप की आवश्यकता थी क्योंकि निवेश करने के लिए काफी बड़ी पूँजी की जरूरत पड़ती थी। ऐसा इस कारण से था कि व्यापार की अनिश्चितता बनी रहती थी (जहाज डूबने, युद्ध आदि के कारण) और पूँजी निवेश करने तथा लाभांश प्राप्त होने के बीच भी काफी लंबे समय की प्रतीक्षा करनी होती थी। क्योंकि व्यापारिक जहाजों को भारत तक आने के लिए संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। इन्हीं कारणों से प्रारंभिक दिनों में अंग्रेज सौदागरों को अपना धन भारत की यात्रा पर जाने के लिए, जहाजों को किराये पर लेने और सुसज्जित करने पर लगाना पड़ता था। इसकी तर्क पूर्ण परिणति संयुक्त स्टॉक उद्यम के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में हुई (1600)। प्रारंभ में लंदन के कुछ बहुत धनी सौदागर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक थे। लेकिन 18वीं सदी के दौरान तुलनात्मक रूप से कुछ छोटे शेयर धारकों ने इसमें भाग लेना शुरू किया और नयी यूनाइटेड कंपनी ऑफ दि मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडिज (1708 में स्थापित) के मालिक बन गए। इसको उसी पुराने नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पुकारा जाता था।

14.3 ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार

ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी संरचनात्मक विशेषता यह थी कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा इसको एकाधिकार प्रदान किया गया था। इस एकाधिकार का क्या तात्पर्य था और इसको क्यों प्रदान किया गया था? सामान्यत: एकाधिकार से तात्पर्य यह है कि भारत तथा हिंद महासागर के अन्य देशों और इससे आगे पूरब की ओर चीन के साथ होने वाले व्यापार पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण को कायम करना। इसके फलस्वरूप उपरोक्त बताए गए देशों के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी (किसी अन्य व्यक्ति या व्यावसायिक फर्म की तुलना में) वैधानिक रूप से व्यापार करने के लिए अधिकृत थी। यह कंपनी का वैध अधिकार था जिसको प्रथम बार महारानी ऐलिजाबेथ ने प्रदान किया और बाद में अन्य राजा प्रदान करते रहे। 17वीं

एवं 18वीं सदी में राजाओं या सरकारों ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिकार को इसलिए प्रदान किया क्योंकि वाणिज्यवादियों के विचारों के प्रभाव के अंतर्गत सामान्यतः यह विश्वास किया जाता था कि विदेशी व्यापार से धन देश के अंदर लाने के लिए राज्य को बाह्य व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे देशों के साथ व्यापार में जोखिम होने से विशेषकर एकाधिकार व्यवस्था को अनिवार्य माना जाने लगा जिससे कि निवेशकर्ताओं के एकाधिकार लाभों को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार इस तरह के निवेश को प्रोत्साहित भी किया गया। दूसरे, भारतीय व्यापार में अपेक्षाकृत धनी सौदागर ब्रिटिश राजा के दरबार एवं सरकार में काफी प्रभावशाली भी थे।

1. ईस्ट इंडिया हाउस

इस सबका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया। यह कंपनी को एक चार्टर के द्वारा दिया गया। दूसरे शब्दों में एकाधिकार के अधिकार को एक लिखित अनुदान के रूप में दिया गया और समय-समय पर इसका सरकार के द्वारा नवीनीकरण किया जाता था। जिस एक्ट के अंतर्गत कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया गया था उसको 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में "चार्टर एक्ट" के नाम से जाना गया और ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। (फ्रांसीसी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनियों को भी एकाधिकार प्राप्त थे और इनको उनकी सरकारों के द्वारा प्रदान किया गया था)।

सरकार द्वारा अनुदानित एकाधिकार की घोषणा एक बात है और वास्तव में एकाधिकार (अर्थात् दूसरों को पूर्णरूपेण अलग कर देना) को प्रभावी बनाना बिल्कुल एक दूसरी बात है। वास्तविक कार्य रूप में इस वैध एकाधिकार का क्या तात्पर्य था?

14.4 एकाधिकार बनाम उन्मुक्त व्यापार

ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च प्रबंधकों को निदेशक मंडल (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) कहा जाता था और उनको 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध से 1813 तक कंपनी को एकाधिकार अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात् दूसरों को व्यापार में प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह कोई आसान कार्य न था। एक अन्य बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने औपचारिक व्यवसाय अर्थात् कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ अपना व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनका यह व्यवसाय कंपनी के हितों से ऊपर नहीं होता था। एक अन्य तथ्य यह भी था कि वहाँ पर सदैव ऐसे सौदागर एवं साहसी लोग थे जो व्यापार के लिए भारत आते तथा अपनी स्वयं की व्यवसाय फर्मों को स्थापित करने में सफल हो जाते, इनको "उन्मुक्त" सौदागर या "बिना अधिकार के

व्यापार करने वाले," (अर्थात् बिना अधिकार के प्रवेश करने वाले अनाधिकृत व्यवसाय में व्यस्त) कहा जाता था। इन दोनों प्रकार की गतिविधियों ने कंपनी के एकाधिकार के रास्ते में अवरोध पैदा किये।

ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों या कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवसाय के विषय में समस्या यह थी कि भारत में स्थित सर्वोच्च अधिकारियों सहित कंपनी के कर्मचारियों के स्वयं के हित इस बात की आज्ञा प्रदान नहीं करते थे कि कंपनी के निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों को कठोरता से लागू किया जाए। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन 19वीं सदी तक काफी कम था तथा व्यक्तिगत व्यापार के लाभ से वेतन में वृद्धि करने की परंपरा का व्यापक प्रचलन था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि कंपनी के सेवक आदतन अपने व्यक्तिगत व्यापार की वस्तुओं को कंपनी निर्यात की वस्तुओं के साथ रख देते थे जिससे कि बंगाल में आंतरिक करों से उनको छूट मिल जाती थी। इसको दस्तक (कर मुक्त व्यापार के लिए लाइसेंस) का दुरुपयोग कहा जाता था और यह बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच विवाद और संघर्ष के कारणों का मुख्य विषय हो गया था (देखें खंड 3)। वास्तव में 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार हित और कंपनी का औपचारिक व्यापार व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे के लिए अविभाज्य हो गए थे।

जहाँ तक "उन्मुक्त सौदागरों" का प्रश्न है, उनका उद्देश्य अपने व्यापार का प्रसार कंपनी के व्यापार के कीमत पर करना था। यद्यपि उनको इसलिए सहन किया गया क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों के लिए वे काफी उपयोगी होते जा रहे थे जिससे कंपनी के कर्मचारी अपने संचित धन का निवेश उनके व्यापार में कर देते और दूसरे उनको लूट का भी भय नहीं रहता था। धन को उन्मुक्त सौदागरों के माध्यम से इंग्लैंड भेजने की सुविधा भी थी। कंपनी के निदेशकों एवं लॉर्ड कार्नवालिस जैसे विवेकशील गवर्नरों ने कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार छोड़ने के लिए दबाव डाला, इस कारण से "उन्मुक्त सौदागरों" को कंपनी के कर्मचारियों से अधिक पूँजी प्राप्त हुई। वे ऐसे कार्य करते कि उनको कंपनी के कर्मचारियों का एजेंट कहा जाता। इसी के साथ उन एजेंसी संगठनों का विकास हुआ जिनको 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रबधक एजेंसीज के नाम से पुकारा जाने लगा।

इसी बीच इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार पर एकाधिपत्य की आलोचना होने लगी। उन्मुक्त व्यापार के जिसको कि एडम स्मिथ (वेल्थ ऑफ नेशंस, 1976) ने प्रचारित किया था, एकाधिकारवादी विरोधी थे। भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अलग किए गए पूँजीपतियों ने स्वाभाविक रूप से उन्मुक्त व्यापार के अभियान का समर्थन किया। इंग्लैंड में पूँजी संचयन निवेश पर लगे प्रतिबंधों से स्वतंत्रता चाहते थे। इससे भी अधिक औद्योगिक क्रांति के जारी रहने से 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक पूँजीपतियों के हित और भी महत्वपूर्ण हो गये । इंग्लैंड की संसद में एक ऐसी शक्तिशाली लॉबी थी जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दबाव बनाए हुए थी। इन परिस्थितियों में 1813 में चार्टर अधिनियम को पारित कर दिया गया जिससे कि भारतीय व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 के दूसरे चार्टर अधिनियम ने चीन के व्यापार में कंपनी के शेष विशेषाधिकार पर एकाधिपत्य को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार, दो सौ वर्षों से भी अधिक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए एकाधिपत्य को सरकार ने वापस ले लिया।

बोध प्रश्न 1

1) संयुक्त स्टॉक कंपनियों के क्या लाभ हैं? पाँच पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

2) "व्यापार के एकाधिपत्य" से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

3) भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिपत्य को कायम रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन-किन चुनौतियों का सामना किया? 100 शब्दों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

14.5 कंपनी के व्यापार की प्रकृति

हमने अभी तक अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किए गए वैध एकाधिपत्य का विवेचन किया। वास्तव में एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। फिर भी, भारत के कुछ भागों में कंपनी और व्यक्तिगत अंग्रेज व्यापारियों को सामूहिक रूप से वास्तव में एकाधिपत्य प्राप्त था। 18वीं सदी के अंतिम दशक से यह बंगाल के बारे में पूर्णरूपेण सत्य था। (इस खंड की इकाई 18 में हम इस इतिहास का विस्तृत विवेचन करेंगे)।

जबकि वाणिज्य पूंजीवादी व्यवसाय का सार सस्ता खरीदना एवं महँगा बेचना है, तब प्रतिस्पर्धा को कम करना व्यापार का स्वाभाविक लक्ष्य होगा। यदि आपका लक्ष्य सस्ता खरीदना है, तब बाजार में खरीदारों का कम होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निश्चय ही यह सस्ता खरीदने में सहायता करता है। इसी प्रकार आप अपने सामान को तभी महँगा बेच पाएँगे जब कम से कम विक्रेता हों। लेकिन वास्तविक जीवन में, पुस्तकों में दी गई एकाधिकारवाद की परिभाषा कि बाजार में एकमात्र खरीददार हो, कार्यरूप में कदाचित् ही सत्य होती हो। अतः परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए शक्ति का प्रयोग, वैधानिकता या प्रतियोगियों को हटाने के लिए युद्ध जैसे साधनों को अपनाया जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया।

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं (खंड 2) कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यवसाय मसालों, नील, सूती कपड़ों आदि उपभोग की वस्तुओं का उपार्जन करना एवं उनका यूरोप को निर्यात करना था। प्रारंभ में इन वस्तुओं का भारत में उपार्जन काफी प्रतियोगी परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया। सत्रहवीं सदी की एक फैक्ट्री की सामान्यतः प्रतियोगिता स्थानीय या देश के सौदागरों और दूसरी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों सहित विदेशी व्यापारियों के साथ होती थी। 18वीं सदी के दौरान अंग्रेजों ने लगातार लाभ की स्थिति को प्राप्त किया। इसके कुछ कारण थे :

i) दूसरी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों की शक्ति को कम कर दिया गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा दूसरी कंपनियों पर सैन्य एवं राजनैतिक विजय प्राप्त करके किया। इसको खंड 3 में उद्धृत किया गया है।

ii) मुगल साम्राज्य के पतन के बाद के उत्तराधिकारी राज्यों एवं रियासतों की कमजोरी ने

ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा अवसर प्रदान किया जिससे रिश्वत तथा बल प्रयोग द्वारा स्थानीय राज्यों से यूरोपीय व्यापारियों को विशेष व्यापार विशेषाधिकारों को लिया जा सके।

iii) कारीगरों (जुलाहों) तथा किसानों (नील उत्पादकों) का सस्ते दाम पर सामान का उत्पादन कराने के लिए 18वीं सदी के अंतिम दशक से ही शोषण किया गया और कंपनी के लिए सामान का उत्पादन करने के लिए उनको बाध्य किया गया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत व्यापार में जिस स्थिति को प्राप्त कर लिया था उसको, यूरोप को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं के प्रति सामूहिक एकाधिकार की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया।

14.6 वाणिज्य व्यवसाय और राजनैतिक शक्ति

अभी तक हमने वाणिज्य पूंजीवादी गतिविधियों की उन विशेषताओं का विवेचन किया है जिनका संकेत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमने इस प्रश्न के विषय में कुछ नहीं कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागरों को क्षेत्रीय प्रसार प्रारंभ करने के लिए किन कारणों ने प्रेरित किया और प्रारंभ में इस प्रसार का राजनीति के साथ क्या संबंध था? व्यापारियों द्वारा भारत के साथ यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ में समय-समय पर एक या अधिक जहाजों से समुद्री यात्राएँ करनी पड़ती थीं। फिर, जब कभी कोई "जहाजी बेड़ा" भारतीय बंदरगाह पर पहुँचता तब संक्षिप्त समय में भारत के अंदर सामान की एक बड़ी मात्रा का उपार्जन करना कोई सरल कार्य न था। इसलिए किसी उत्पादन केंद्रों के बड़े समुद्रीय बंदरगाहों के पास फैक्ट्रियों को स्थापित करना आवश्यक हो गया। आपको यह समझ लेना चाहिए कि ये आज की उन फैक्ट्रियों की भाँति नहीं थी जहाँ पर वास्तविक उत्पादन किया जाता है, 17वीं एवं 18वीं सदियों में अंग्रेजी में फैक्ट्री शब्द का अर्थ था कि किसी बिदेशी कंपनी द्वारा विदेशी व्यापार के केंद्रों की स्थापना करना। जिन अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी उनको "फैक्टर्स" कहा जाता था और ये अनिवार्य रूप से वेतनभोगी एजेंट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से निर्यात के लिए सामान की खरीददारी करते थे। अब, अन्य ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ-साथ अंग्रेजी कंपनी भी इन फैक्ट्रियों के चारों ओर किलों का निर्माण कर इनको सुरक्षित करना चाहती थी। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की क़िलेबंदी करना संभवत: आवश्यक हो गया था और कुछ स्थानीय सरकारों ने मूक रूप से या स्पष्ट तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमि प्राप्त करने तथा किलों के निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन कंपनियों ने आत्म-रक्षा की वैधानिकता की सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी एवं सैन्यकरण इस ढंग से किया कि वे स्थानीय सरकारों को चुनौती देने वाले सैन्य केंद्र बन गए। कलकत्ता का फोर्ट विलियम तथा मद्रास का फोर्ट सैंट जॉर्ज इस के प्रमुख उदाहरण थे। (देखें खंड 3)। इस प्रकार किलों ने विदेशी सौदागरों को एक ऐसा केंद्र उपलब्ध करा दिया जहाँ से उनको पड़ोसी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण फैलाने का अवसर प्राप्त हो गया। कभी-कभी कंपनी के क्षेत्रीय दावों का आधार वैध होता था (जैसे कि बंगाल में कंपनी को जमींदारी अधिकारों को प्रदान किया गया)। लेकिन अपवाद को छोड़कर 18वीं सदी के अंतिम दशकों में क्षेत्रीय दावों का वास्तविक आधार कंपनी की सैन्य शक्ति था। आप पहले से जानते हैं कि 18वीं सदी के मध्य से यूरोपीय कंपनियों ने कैसे क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में कार्य किया (खंड 3)।

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विकास चरणों में हुआ। जहाजी बेड़े की व्यवस्था से "फैक्ट्री व्यवस्था, फिर उसके बाद किलेबंदी की व्यवस्था और वहाँ से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विकसित होकर कंपनी ने अपने व्यापार में अत्याधिक वृद्धि की। कंपनी की राजनीतिक के विस्तार की यह प्रक्रिया काफी जटिल थी। उदाहरणस्वरूप सैन्य शक्ति का रखना कंपनी की राजनीतिक अनिवार्यता थी। सस्ती कीमतों पर सामान का उत्पादन कराने के लिए कारीगरों (अर्थात् बंगाल के जुलाहों) का दमन करने में इस सैन्य शक्ति ने मदद की, स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के एजेंटों और व्यक्तिगत व्यापारियों का बिचौलिया बनाने में तथा अन्य विदेशी सौदागरों को विशेषकर फ्रांसीसियों एवं डचों को) अंग्रेज व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता से अलग करने में भी इस सैन्य शक्ति की उपयोगिता रही। इसके अलावा, एक सैन्य तथा क्षेत्रीय शक्ति स्थानीय रियासतों से रिश्वत तथा धन वसूल

कर सकती थी तथा युद्धों में लूट के द्वारा भी धन अर्जित किया जा सकता था। अंततः राजनैतिक शक्ति पर नियंत्रण से राजस्व पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका उत्तम उदाहरण 1765 में बंगाल की दीवानी का प्राप्त हो जाना था। बंगाल के भू-राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी हो जाने से इंग्लैंड से भेजी जाने वाली सोने-चाँदी की मात्रा को वर्षों तक कम कराने में कंपनी सफल हो गई। कंपनी द्वारा निर्यात करने के लिए भारत में सामान को खरीदने में चाँदी की आवश्यकता होती थी। निश्चय ही कंपनी की यह इच्छा थी कि इंग्लैंड से निर्यात होने वाली चाँदी को कम किया जाए तथा यह तभी संभव था जबकि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अदायगी नकद पैसे के द्वारा की जाए। कंपनी की राजनैतिक अभिलाषाओं में बहुत से आर्थिक हित निहित थे और यही अंग्रेजों के हितों के लक्ष्य थे। इससे आप समझ सकते हैं कि 18वीं सदी में भारत के राजनैतिक इतिहास में कंपनी ने कैसे एक प्रबल भूमिका अदा की और 19वीं सदी के प्रारंभ में उसका उद्भव सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ।

14.7 औद्योगिक पूँजीवाद का उदय और कंपनी की वाणिज्यिक नीतियाँ

1750 में इंग्लैंड में राष्ट्रीय आमदनी का लगभग 40 से 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में पैदा किया जाता था, 1851 तक कृषि का भाग 20 प्रतिशत तक कम हो गया और 1881 तक यह राशि 10 प्रतिशत तक आ गई। इंग्लैंड की राष्ट्रीय आमदनी में विदेश व्यापार का योगदान 1790 में 14 प्रतिशत था, 1880 में यह 36 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह इंग्लैंड में औद्योगीकरण की तेज गति का सूचक है। इसने इंग्लैंड को 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। (खंड 2 में इस रूपातंरण के कुछ पक्षों का विवेचन किया गया था)। इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पाद तथा इस उत्पाद में विदेश व्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता प्राप्त कर ली। विशेषकर अंग्रेजी सूती कपड़ा उद्योग के विकास का स्पष्टतः अर्थ था कि इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़ों की माँग का अन्त। उसी के साथ-साथ इंग्लैंड अब भारत तथा अन्य देशों में अपने सूती कपड़ों के लिए बाजार की तलाश कर रहा था।

औद्योगिक सामान को तैयार करने के लिए अब इंग्लैंड को पहले से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी, उदाहरण के रूप में, औद्योगीकरण के बाद इंग्लैंड भारत एवं अन्य देशों से कपास का आयात करने लगा। इस प्रकार अंग्रेजी औद्योगक क्रांति से पूर्व अर्थात् वाणिज्य पूँजीवाद के युग में भारत और इंग्लैंड के बीच आर्थिक रिश्तों का जो आधार था उसकी तुलना में औद्योगिक क्रांति के बाद इन रिश्तों का संपूर्ण आधार भिन्न हो गया था।

संक्षेप में, इंग्लैंड के प्रथम औद्योगिक पूँजीवादी देश में रूपांतरण हो जाने से व्यापारी कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय साम्राज्य की भूमिका में भी बदलाव आया। सौदागरों की कंपनी तथा उनका साम्राज्य इन नयी परिस्थितियों में एक नवीन भूमिका की ओर अग्रसर हो रहा था। इस अध्याय में जिस काल अर्थात् 1887 तक के समय का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें नए साम्राज्यवाद के प्रारंभ को देखा जा सकता है। इस समय में भारतीय उत्पादित सामान के इंग्लैंड को होने वाले निर्यात में कमी आई। भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले कपड़ों का मूल्य 1815 में 13 लाख पौण्ड था, लेकिन यह निर्यात कम होकर मात्र एक लाख पौण्ड मूल्य का रह गया। ठीक इसी के दौरान इंग्लैंड से भारत को आयात होने वाले सूती कपड़ों में 15 गुणा वृद्धि हुई। इससे पूर्व शताब्दी में कंपनी की वाणिज्य नीति की प्रधानता निर्यात के लिए भारत में सूती वस्त्रों को खरीदना थी। 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में उपार्जन या खरीददारी को स्वाभाविक रूप में बन्द कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक जीवन के अंतिम दिनों में अर्थात् 1820 के दशक में इसके द्वारा इंग्लैंड को कपास से निर्मित किसी भी उत्पाद का निर्यात नहीं किया गया। जिन वस्तुओं का निर्यात किया गया उनमें केवल कच्ची रेशम, शोरा या बारूद के लिए कच्चा माल, कृषि उत्पाद के रूप में नील, और (एक मात्र उत्पादित वस्तु) रेशम के वस्त्रों की बहुत कम मात्रा निर्यात की जाती थी। जहाँ तक इंग्लैंड में आयात का प्रश्न है, कंपनी ने 1824 से इसको पूर्णतः बन्द कर दिया, वह केवल सैनिक सामान का आयात करती थी और इसका वह स्वयं ही उपयोग करती। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार कंपनी के हाथों से निकलकर व्यक्तिगत व्यापारियों के हाथों में चला गया, जैसा कि आप 1813 के चार्टर अधिनियम से जानते हैं कि भारतीय

व्यापार को पूर्णतः व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।

कंपनी की नीतियों एवं वित्त में एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 19वीं सदी के प्रथम दशकों में हुआ। यह कंपनी की गैर-व्यापारिक आमदनी में वृद्धि होना था, अर्थात् इसको क्षेत्रीय राजस्व कहा जाता था और इसको भू-राजस्व तथा कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों से दूसरे कर वसूल करके प्राप्त किया जाता था। उसी समय व्यापारिक आमदनी में गिरावट आयी क्योंकि, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इन वर्षों में कंपनी के व्यापार में समापन बिन्दु तक कमी आई। इस तरह से 1820 से कंपनी क्षेत्रीय राजस्व पर निर्भर करने लगी जबकि 1765 तक उसकी आमदनी केवल व्यापारिक लाभ से आती थी। 1765 से कंपनी के द्वारा बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाने पर, क्षेत्रीय राजस्व में वृद्धि होने लगी तथा इसी के साथ व्यापारिक आमदनी में कमी आयी। इस प्रकार कंपनी का वित्त एक व्यापारिक कार्पोरेशन का एक क्षेत्रीय शक्ति में हुए रूपांतरण को प्रतिबिम्बित करता था।

अंत में यह समझा जा सकता है कि कंपनी के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व को व्यापारिक उद्देश्यों की ओर मोड़ना उसकी एक सोची-समझी नीति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से कंपनी बंगाल सरकार का भी एक हिस्सा थी और ठीक उसी समय वह एक व्यापारिक कंपनी भी थी। बंगाल के राजस्व के एक पर्याप्त भाग का उपयोग इंग्लैंड को निर्यात करने वाले सामान के खरीदने पर किया जाता और इसको भी "निवेशीकरण" का नाम दिया जाता। जैसा कि 1783 में इसके विषय में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति ने कहा भी, "इस तरह का निवेशीकरण" बंगाल में लाई गई व्यापारिक पूंजी को वास्तविक रूप में खर्च करना न था, अपितु यह "एक नजराने की अदायगी" का साधन मात्र था। यहाँ भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा कहे जाने वाले "आर्थिक निकास" का एक विशेष उदाहरण था। इस क्षेत्रीय राजस्व के बल पर कंपनी को उधार में धन की प्राप्ति हो जाती थी (इसको क्षेत्रीय ऋण कहा जाता था) और इसकी अदायगी उस सैनिक कार्रवाई के लिए की जाती जो आगे क्षेत्रीय प्रसार के लिए होती थी।

बोध प्रश्न 2

1) उन कारणों की सूची बनाइए जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय एवं राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

....

....

....

....

....

2) औद्योगिक क्रांति के द्वारा कंपनी की वाणिज्य नीति में क्या परिवर्तन किए गए? 100 शब्दों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

....

....

3) निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके सम्मुख सही (✓) या गलत (✕) का निशान लगाइए।

i) 1813 के चार्टर अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सामाप्त करने के लिए पारित किया।

ii) 17वीं एवं 18वीं सदियों में अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित की गई फैक्ट्रियां विदेशी व्यापारिक केंद्र थे।

iii) ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज्य शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया क्योंकि स्थानीय शासक देश का उचित प्रकार से प्रशासन चलाने में असफल हुए।

iv) इंग्लैंड में औद्योगीकरण ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच आर्थिक रिश्तों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया।

iiv) 19वीं सदी के प्रारंभ में क्षेत्रीय राजस्व से होने वाली कंपनी की आमदनी में व्यापारिक लाभ की तुलना में वृद्धि हुई।

14.8 सारांश

इस इकाई में आपने ईस्ट इंडिया कंपनियों की संरचना का संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में अध्ययन किया और आपने देखा कि किस ढंग से उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने उन्हें एकाधिकार विशेषाधिकारों को प्रदान किया। लेकिन 18वीं सदी के दौरान इस एकाधिकार को व्यक्तिगत व्यापार ने पर्याप्त मात्रा में कमजोर कर दिया था। एकाधिकारवादी कंपनी तथा उन्मुक्त व्यापारियों के मध्य हुए संघर्ष के कारण वैध एकाधिकार व्यापार के अधिकार को वापस लेना पड़ा। व्यवहारिक तौर पर, एक सामूहिक एकाधिकार स्थिति को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा कंपनी के कर्मचारियों ने 18वीं सदी के अंतिम दशकों से भारत के कुछ हिस्सों में मुख्य निर्यात उपभोग वस्तुओं के संदर्भ में प्राप्त किया। यह अंग्रेजी कंपनी के राजनैतिक प्रभुत्व तथा क्षेत्रीय प्रसार के बढ़ने के साथ संयुक्त रूप से संवर्धित था। 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड के औद्योगिक रूपांतरण के कारणवश कंपनी की वाणिज्य नीतियों में व्यापक परिवर्तन हुए। बहुत से वैधानिक उपायों के कारण ब्रिटिश सरकार का कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ता गया क्योंकि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस खंड की इकाई 18 में हम कंपनी के भारत में व्यापार की विशेषताओं एवं परिणामों की विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे।

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखें भाग 14.2

2) देखें भाग 14.3

3) आपको अपने उत्तर में कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार की वृद्धि, उन्मुक्त सौदागरों की भूमिका, उन पूँजीपतियों को जो उन्मुक्त व्यापार आदि का समर्थन करते थे, उद्धृत करना चाहिए। देखें भाग 14.4

बोध प्रश्न 2

1) देखें भाग 14.6

2) आपके उत्तर को भारतीय उत्पादित माल के इंग्लैंड को होने वाले निर्यात में कमी, भारत से इंग्लैंड को बढ़ता माल का निर्यात, भारत के बाजार में अंग्रेजी उत्पादित माल का बढ़ता निर्यात, कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व में वृद्धि आदि पर केन्द्रित होना चाहिए। देखें भाग 14.7

3) i) ✓ ii) iii) iv) ✗ v) ✓